मुरादनगर में गंगनहर पुलिस चौकी में घुसकर कांवड़ियों ने किया हंगामा, गाड़ी में की तोड़फोड़

हिन्दी साप्ताहिक

हर्षिता टाइम्स

RNI Regn. No. UTTHIN/2008/28646

उत्तराखंड में हुई भारी बारिश के दौरान एसडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया

• वर्ष : 16 • अंक : 30 • देहरादून • वृहस्पतिवार 01 अगस्त, 2024 • मूल्य : 1 रुपये • वार्षिक : 50 रुपये • पृष्ट : 4

नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने हिमालयी राज्यों के लिए विशिष्ट नीतियां बनाने का किया अनुरोध

ऊर्जा की कमी को पूरा करने हेतु राज्यों को 25 मेगावाट से कम क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के अनुमोदन तथा क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान करने का किया अनुरोध

लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए प्रस्तावित 24 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी के प्रस्ताव को पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ही हिमालयी राज्यों में भी लागू करने का किया अनुरोध

'पी.एम कृषि सिंचाई योजना' की गाईडलाइन्स में लिफ्ट इरिगेशन को शामिल करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में प्रतिभाग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में उत्तराखण्ड भी निरंतर कार्य कर रहा है। उत्तराखण्ड आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील राज्य है, इस बार के केन्द्रीय बजट में इसको दृष्टिगत रखते हुए विशेष वित्तीय प्राविधान किये जाने पर उन्होंने पीएम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स रैंकिंग में उत्तराखण्ड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो राज्य के लिए गर्व का विषय है। सीएम ने कहा कि पीएम के मार्गदर्शन में राज्य ने 'समान नागरिक संहिता' विधेयक को उत्तराखण्ड में पारित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कई शहरों में पेयजल का गंभीर संकट दिखाई दिया है, इस समस्या के समाधान के के लिए भू जल स्तर बढ़ाने के साथ-साथ जल संरक्षण पर विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। उत्तराखण्ड में इसके लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिज्यूविनेशन ऑथोरिटी का गठन किया है, जो जल संरक्षण और जल स्रोतों को पुनजह्वित करने और हिम आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़े जाने की परियोजना पर कार्य कर रही है। उन्होंने इसके लिए केन्द्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता एवं तकनीकि सहयोग का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसके लिए कलस्टर आधारित इंक्यूबेशन सेंटर तथा ग्रोथ सेंटर महत्वपूर्ण साबित होंगे। उत्तराखण्ड में पायलट प्रोजक्ट के रूप में दो रूरल इंक्यूबेशन सेंटर तथा 110 ग्रोथ सेंटर स्थापित किये गये हैं। उन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से तकनीकि और वित्तीय सहयोग के लिए अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को 25 मेगावाट से कम क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के अनुमोदन तथा क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान करने तथा लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए प्रस्तावित 24 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी के प्रस्ताव को पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ही हिमालयी राज्यों में भी लागू करने का अनुरोध किया। 'पी.एम कृषि सिंचाई योजना' की गाईडलाइन्स में लिफ्ट इरिगेशन को शामिल करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग तथा क्लाईमेट चेंज जैसे विषयों पर भी हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके दृष्टिगत उत्तराखण्ड सरकार ईकोलॉजी और ईकॉनॉमी के समन्वय से विकास योजनाओं को संचालित करने पर विशेष ध्यान दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी विकसित राष्ट्र में उनके शहरी क्षेत्र ग्रोथ इंजन के रूप में विशेष योगदान देते हैं। रोजगार सृजन बड़े शहरों में अधिक होता है, जिस कारण इन शहरों में अत्यधिक जनसंख्या के कारण मूलभूत सुविधाएं देना कठिन हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए देश के विभिन्न शहरों के बीच 'काउंटर मैग्नेट एरियाज' विकसित करने होंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना शोध विकास एवं नवाचार के लिए ए.आई रेडीनेस और क्वांटम रेडीनेस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष नीति आयोग की 8वीं बैठक में हिमालयी राज्यों के विकास संबंधित कुछ प्रस्ताव रखे गये थे, उन प्रस्तावों पर हिमालयी राज्यों के परिपेक्ष में विशिष्ट नीतियां बनाने का उन्होंने अनुरोध किया।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की

देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा उनके नाम व मोबाइल नंबर अविलंब शासन को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभिन्न अवसरों पर सरकारी कार्यक्रमों में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके उत्तराधिकारियों के साथ बैठक की।

मुख्य सचिव ने बैठक में उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों की समस्याओं की जानकारी ली तथा त्वरित समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने इस दिशा में जिलाधिकारी चमोली द्वारा बेहतरीन कार्य करने के लिए सराहना की।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों कि स्मृति में सड़कों, चौराहों व द्वारों के नामकरण तथा शिलापट स्थापित किए जाने संबंधित प्रकरणों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारी के विभिन्न प्रकरणों के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

बैठक में सभी संबंधित विभागों के सचिव, वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी व स्वतंत्रता सेनानी तथा उनके उत्तराधिकारी उपस्थित रहे

मुख्यमंत्री धामी ने कोचिंग सेंटरों के लिए गहन निरीक्षण के आदेश दिए

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में संचालित कोचिंग सेंटरो की गहनता से जांच के निर्देश दिये है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोचिंग सेंटरों में अध्यनरत छात्रों एवं अध्यापकों आदि के लिए की गई व्यवस्थाओं का भी स्थलीय निरीक्षण किया जाए। उन्होंने इसके लिए प्रदेश व्यापी अभियान संचालित करने के भी निर्देश मुख्य सचिव को दिये है। कोचिंग सेंटरों में पार्किंग व्यवस्था तथा आसपास यातायात की सुगमता पर भी ध्यान दिये जाने की बात कही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भारी वर्षा के दृष्टिगत जल भराव होने की सम्भावना रहती है। अत: ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की आपदा के त्वरित निराकरण हेतु राज्य में संचालित विभिन्न कोचिंग सेन्टर एवं ऐसे भवन जिनके बेसमेंट में विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियां संचालित हो रही हैं की तत्परता तथा प्राथमिकता के साथ जांच कर उनमें सुधारात्मक कार्यवाही की जाए ताकि किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान से बचा जा सके।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को राज्य में संचालित विभिन्न कोचिंग सेन्टर एवं ऐसे भवन जिनके बेसमेन्ट में विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियां संचालित हो रही हैं, की जांच के निर्देश दिए है। इस संबंध में जारी निर्देश में मुख्य सचिव ने कहा है कि मानसून के दौरान अतिवृष्टि के कारण नई दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कोचिंग सेन्टर के बेसमेन्ट में जलभराव की स्थिति के कारण हुई अप्रिय घटना के दृष्टिगत उत्तराखण्ड में संचालित विभिन्न कोचिंग सेन्टर एवं ऐसे भवन जिनके बेसमेन्ट में विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों संचालित हो रही हैं, की जांच भवन उप-नियमों और सुरक्षा सम्बन्धी अन्य मानकों/नियमों के तहत शीर्ष प्राथमिकता के साथ करना सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने जिलाधिकारियों को सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ तत्काल बैठक कर जनपद में सभी कोचिंग सेंटरों के निरीक्षण हेतु एक समिति का गठन कर समिति के माध्यम से वर्णित स्थानों की जांच कराते हुए सभी प्रकार की कमियों का निराकरण सुनिश्चित कराने को कहा है। जिन भवनों में कमियों का निराकरण किया जाना संभव नहीं हो पा रहा हो, उन भवनों में मानसून अवधि तक के लिए ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाये जाने हेतु निर्देश दिये हैं।

उन्होंने ऐसे भवन जिनके बेसमेंट में विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों संचालित हो रही है में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच तथा भवन अथवा कोचिंग सेंटर में उपलब्ध अग्निशमन यंत्र एवं अलार्म तथा किसी आगजनी की घटना में निकासी मार्ग को स्पष्ट रूप से चिन्हित करने को कहा है। ऐसे भवनों में स्थापित विद्युत प्रणाली की जांच विद्युत सुरक्षा विभाग से कराने तथा आवश्यक अनुमति/प्रमाण-पत्र भवन स्वामी द्वारा लिये जाने, विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा सुझाये गये उपायों का समावेश भवन में स्थापित विद्युत प्रणाली में किये जाने तथा भवन निर्माण के लिए आवश्यक मानकों की पूर्ति की भी जांच करने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिए।

"21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हरसंभव प्रयास।
आज उत्तराखण्ड, इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। ये दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा।"

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

"प्रधानमत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखण्ड समय के साथ परिवर्तनकारी विकास का साक्षी बन रहा है। अत्याधुनिक रोपवे परियोजनाओं के साथ-साथ रेलवे, सड़क और हवाई संपर्क की दिशा में प्रगति हो रही है। इससे उत्तराखण्ड में यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। ये बदलाव न केवल पर्यावरण अनुकूल हैं, बल्कि कुशल परिवहन भी सुनिश्चित करते हैं। ये राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देते हैं। आध्यात्मिक, रोमांचक और सांस्कृतिक पर्यटन के प्रभाव के चलते यह दुनिया भर के आगंतुकों के लिए एक पंसदीदा गंतव्य बन रहा है। हम सतत विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए एक समृद्ध कल की ओर देख रहे हैं।"

जय हिन्द-जय उत्तराखण्ड

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

विकसित भारत, विकसित उत्तराखण्ड

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट - 2023 के दौरान राज्य सरकार के साथ कुल 3.5 लाख करोड़ रुपये के हुए निवेश समझौते। जिसमें 81 हजार करोड़ के समझौते की ग्राउण्डिंग।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में श्री केदारनाथ धाम का हुआ भव्य एवं दिव्य पुनर्निर्माण कार्य। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत विकास कार्य गतिमान।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आदि कैलाश और जागेश्वर धाम के दर्शन के बाद मानसखंड यात्रा को मिली नई पहचान।
- चार धामों की कनेक्टिविटी के लिए ऑल वेदर रोड का हुआ निर्माण। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेललाइन का निर्माण कार्य तथा टनकपुर-बागेश्वर रेललाइन सर्वे का कार्य गतिमान।
- नैनीताल जिले की बहुद्देशीय जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत मिली मंजूरी।
- उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम की लखवाड़ परियोजना को मिली मंजूरी।
- उत्तराखण्ड को दो वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात। देहरादून से दिल्ली एवं देहरादून से लखनऊ का सफ़र हुआ आसान।
- दिल्ली - देहरादून के बीच एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य तेजी से जारी, 2 से 2.5 घंटे में सफर होगा पूरा।
- पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिये पर्वत माला परियोजना को मिली मंजूरी। केदारनाथ, हेमकुंड साहिब एवं पूर्णागिरी मंदिर तक रोपवे के निर्माण कार्य का हुआ शिलान्यास।
- उधमसिंहनगर के किच्छा क्षेत्र में एम्स के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य गतिमान। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखण्ड के सीमांत गावों का हो रहा चहुँमुखी विकास।
- जौलीग्रांट एयरपोर्ट एवं पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने हेतु कार्य गतिमान।
- प्रधानमंत्री ने दिया वेड - इन - उत्तराखण्ड का मंत्र। जिसके तहत राज्य सरकार नए वेडिंग डेस्टीनेशन का कर रही निर्माण।

नीति आयोग भारत सरकार की ओर से एसडीजी 2023-24 की रिपोर्ट जारी की गई है।
रिपोर्ट में उत्तराखण्ड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खरा उतरते हुए पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है।

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी।
www.uttarainformation.gov.in uttarakhandDIPR DIPR_UK uttarakhand DIPR

भूस्खलन की चपेट में आने से मां बेटी की मलबे में दबने से हुई मौत

देहरादून। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन का क्रम भी बदस्तूर जारी है। टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक के तोली गांव में भूस्खलन की चपेट में आए एक मकान के अंदर मां और बेटी की सोते हुए ही दबकर मौत हो गई। परिवार के अन्य सदस्यों ने देर रात किसी तरह बाहर भाग कर जान बचाई।

सरिता देवी पत्नी वीरेंद्र सिंह, उम्र 40 वर्ष व अंकिता, उम्र 15 वर्ष, ग्राम तोली के शव मलबे से बरामद कर जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व पुलिस की टीम तोली गांव पहुंच गई है। वहीं भारी बारिश के चलते भिलंगना ब्लॉक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है।

तोली गांव के ग्राम प्रधान रमेश जिरवाड़ ने बताया, ''रात को दो-ढाई बजे क्षेत्र में जमकर बारिश हुई। इसी दौरान ग्रामीण वीरेंद्र लाल का मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया। मकान के पीछे से हुए भूस्खलन में दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। घर के अंदर सो रही वीरेंद्र लाल की पत्नी सरिता देवी, 36 वर्ष और उसकी बेटी अंकिता, 15 साल अंदर मालबे में दब गई है''।

एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर रविंद्र सजवान ने बताया, ''एसडीआरएफ द्वारा सुबह चलाए गए बचाव अभियान में डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद लापता दोनों महिलाओं का शव बरामद किए गए''।

आपदा प्रबंधन विभाग के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, तिनगढ़ गांव का जूनियर हाई स्कूल भवन भी भूस्खलन से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। विशन गांव, दला गांव को जोड़ने वाला पैदल पुलिया भी बह गई है।

सेनानायक एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा ने भारी बारिश की दृष्टिगत एसडीआरएफ टीम को बूढ़ा केदार क्षेत्र में ही कैंप करने के लिए निर्देशित किया गया है।

एबीवीपी महानगर की कार्यकारिणी घोषित

देहरादून। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् महानगर की एस.जी.आर.आर. महाविधालय सभागार में की महानगर कार्यकारणी की घोषणा कार्यक्रम रहा, प्रांत संगठन मंत्री अंकित सुन्दरियल, विभाग प्रमुख डॉ कौशल कुमार, विभाग संगठन मंत्री नागेंद्र बिष्ट, महानगर अध्यक्ष डॉ जेवीएस रौथान, महानगर मंत्री उज्ज्वल सेमवाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें कार्यक्रम की प्रस्ताविकी डॉ जेवीएस रौथन व महानगर मंत्री सत्र 2023-24 की मंत्री प्रतिवेदन सभी के बीच रखा तथा विभाग प्रमुख डॉ कौशल कुमार ने संगठन में कार्यकारणी का महत्व बताया संगठन में राष्ट्र प्रथम संगठन द्वितीय व्यक्ति अंतिम के विचार पर कार्य करना चाहिए।

चुनाव अधिकारी रमाकान्त श्रीवास्तव ने नवीन सत्र में डॉ जेवीएस रौथान को पुनः महानगर अध्यक्ष तथा नव निर्वाचित महानगर मंत्री पर यशवंत की घोषणा की गई। जिसके बाद महानगर अध्यक्ष ने अपनी कार्यकारणी की घोषणा की जिसमें महानगर उपाध्यक्ष डॉ सुमंगल सिंह, डॉ प्रगति वर्थवाल, डॉ मोनिका भटनाकर, डॉ ज्योति सिंगर, महानगर सह मंत्री पार्थ जुयाल, रोविन तोमर, काजल पयाल, वंशिका राणा, दक्ष शर्मा, महानगर कोषाध्यक्ष डॉ विजय बहुगुणा, स्टडी सर्कल संयोजक शिवानी रावत, सहसंयोजक इरम फ़ातिमा, मीडिया संयोजक अलंकृत सेमवाल, सहसंयोजक रोहित, आंचल, सोशल मीडिया संयोजक प्रीतम सेमवाल, सहसंयोजक रितेश रावत, दिव्यांश शर्मा, महानगर छात्रावास संयोजक निखिल तोमर, सहसंयोजक अर्पित गोस्वामी, सुप्रिया यादव, राष्ट्रीय कला मंच अंकित थापा, सह संयोजक रचना महर, एसएफडी संयोजक यशप्रताप बिष्ट, साधना रतूड़ी, अनुभूति शर्मा, एसएफएस संयोजक रितिक रावत, सह संयोजक सचिन चमोली, सृष्टि रतूड़ी, खेलों भारत संयोजक चन्द्र शेखर, सह संयोजक अरमान डोभाल, गौरव राणा, इण्डोजीनस संयोजक डोली शर्मा, एग्रीविजन संयोजक आयुष डिमरी, निजी विवि कार्य संयोजक अमन जोशी कुश सचदेवा, निजी महाविद्यालय कार्य संयोजक अंशुल बहुगुणा, खुशी जोशी, स्कूली कार्य संयोजक उदित मौर्य, सह संयोजक सचिन नेगी, अभय, महानगर एन.सी.सी. कार्य संयोजक राघवी चौधरी, विशेष आमंत्रित सदस्य डॉ राम विनय शर्मा, डॉ गीता तिवारी, डॉ शैली गुप्ता, डॉ कंचन, की घोषणा की गई।

समापन समारोह में प्रदेश संगठन मंत्री अंकित सुन्द्रियाल ने संगठन मजबूती कार्यकर्ता विकास के विषय पर मुख्य रूप से जोर दिया तथा विद्यार्थी परिषद की सामाजिक विषयों के साथ साथ गतिविधि आयामों के रचनात्मक स्वरूप के माध्यम से विद्यार्थियों को जोड़ना एवं अभविप का चौमुखी विकास पर प्रकाश डाला।

सभागार में प्रदेश अध्यक्ष डॉ ममता सिंह, प्रदेश मंत्री ऋषभ रावत, मंच संचालन चंदन नेगी, नितिन चौहान, राहुल जुयाल, बलवीर कुंवर, आकाश सिंह, साहिल, ऋषभ मल्होत्रा, रितिक नौटीयाल, नवदीप राणा, देवेंद्र दानु अमन तोमर, दिव्यांशु नेगी, ज़िला संयोजक अर्जुन नेगी, आयुषी पेन्युली, प्रियांशु खत्री, आदि उपस्थित थे।

सम्पादकीय

अतिवृष्टि की संभावनाओं के साथ तैयार रहें

भारतीय मौसम का दृश्य अक्सर अप्रत्याशित घटनाओं से भरा रहता है। वर्षाओं के दौरान अतिवृष्टि विशेष रूप से विपणी क्षेत्रों और गांवों को प्रभावित करती रही है, जिससे गहरे आर्थिक और सामाजिक प्रभाव होते हैं। हाल ही में, उत्तराखंड प्रदेश में भी अतिवृष्टि से जुड़ी चिंताएं बढ़ी हैं।

उत्तराखंड का मौसम अप्रत्याशितता का प्रतीक बन चुका है। यहां के पहाड़ी इलाकों में बारिश की मात्रा अक्सर अधिक होती है, जिससे जलभराव और भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों में अतिवृष्टि से जुड़ी घटनाओं की संख्या बढ़ी है, जिनमें विशेष रूप से बाढ़, भूस्खलन, और मृतकों की संख्या का वृद्धि शामिल है। इस स्थिति में, सरकारों और सामाजिक संगठनों को साथ मिलकर उत्तराखंड की जनता की सुरक्षा और सुरक्षितता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रहना होगा।

अतिवृष्टि के प्रकोप से जुड़ी विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले, यह अप्रत्याशित वर्षा की मात्रा और दिन-रात की सुरक्षा उपायों की जांच और सुधार के लिए सरकारी विभागों और वैज्ञानिक संस्थाओं को समय-समय पर जानकारी देने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। दूसरे, अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में अवरुद्धता की स्थिति का अधिक ध्यान देना चाहिए, ताकि वहां की जनता सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित की जा सके।

तीसरा, विकास की दृष्टि से, अतिवृष्टि प्रबंधन की दृष्टि से स्थानीय समुदायों के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए लंबे समय तक सस्ते और प्रभावी उपाय शामिल करने चाहिए। उचित और विकसित सुरक्षा अवधारणाओं को संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाना चाहिए, ताकि जनता की अवरुद्धता को कम से कम किया जा सके।

अतिवृष्टि के प्रकोप से जुड़ी संभावनाओं को समझना और उसके निपटाने के लिए समुदाय के साथ साझेदारी करना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। इस संबंध में, नैतिक और सामाजिक दायित्व है कि हम सभी अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें और स्वीकार करें। अतिवृष्टि से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए उचित समर्थन और सुरक्षा प्रदान करना अनिवार्य है, ताकि हम साथ मिलकर अप्रत्याशित घटनाओं के खिलाफ तैयार रह सकें।

उत्तराखंड में वन्यजीव तस्करों का पर्दाफाश 3 गिरफ्तार, 14 किलो हाथी दांत बरामद

देहरादून/हरिद्वार। उत्तराखंड में वन्यजीव अंगों की अवैध तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में उत्तराखंड एसटीएफ और तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर के साथ श्यामपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में हरिद्वार जिले से दो अंतर्राज्यीय वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार माफियाओं में गौतम सिंह और चन्दन सिंह निवासी ग्राम आमगारपुर, थाना मण्डावली, जनपद बिजनौर (यूपी) शामिल हैं, जिनके पास से 7 किलो वजनी हाथी दांत बरामद किया गया।

विस्तृत पूछताछ के बाद ग्राम नौरंगाबाद श्यामपुर निवासी तस्कर जितेन्द्र सिंह को भी देर रात दूसरे हाथी दांत के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्कर यूपी बिजनौर और हरिद्वार के निवासी हैं और लंबे समय से वन्यजीव अंगों की तस्करी में लिप्त थे।

एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि हरिद्वार क्षेत्र में वन्यजीव तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कुल 14 किलो वजन के दो हाथी दांत के साथ तीन शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार 27 जुलाई 2024 को जब तस्कर हाथी दांत बेचने के लिए निकले, तब एसटीएफ ने कार्रवाई कर दो तस्करों को शाम में और एक को देर रात गिरफ्तार किया।

पकड़े गए तस्करों ने कब, कहां और किस जंगल में हाथी का शिकार किया, यह पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। हाथी को वन्यजीव जन्तु संरक्षण अधिनियम की पहली अनुसूची में रखा गया है, और इसका शिकार करना एक गंभीर अपराध है। आरोपियों के खिलाफ श्यामपुर थाने में वन्यजीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

सुरक्षाबलों ने घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम, एक आतंकी ढेर

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा सुरक्षाबलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है और दो जवानों के घायल होने की सूचना मिली है। कुपवाड़ा के माछिल क्षेत्र में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है।

भारतीय सेना के चिनार कश्वर्प्स ने जानकारी देते हुए बताया कि नियंत्रण रेखा पर माछिल सेक्टर के कामकारी में एक चौकी पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी। जिसमें हमारे दो सैनिक घायल हुए हैं और उन्हें निकाल लिया गया है।

सलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों पर आधारित पुस्तक 'वो 17 दिन' का सीएम ने किया विमोचन

नई दिल्ली। नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'वो 17 दिन' पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक 'वो 17 दिन' सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा सुरंग को लेकर अपने अनुभव भी साझा किए और कहा कि 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालना एक बड़ी उपलब्धि है।

इस अवसर पर भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष श्याम जाजू, पूर्व सांसद डॉ. रीता बहुगुणा जोशी और पुस्तक के लेखक राजीव रंजन सिंह उपस्थित रहे।

सलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों पर आधारित पुस्तक 'वो 17 दिन' का सीएम ने किया विमोचन

नई दिल्ली। नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'वो 17 दिन' पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक 'वो 17 दिन' सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों पर आधारित है।

मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा सुरंग को लेकर अपने अनुभव भी साझा किए और कहा कि 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालना एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन से ही बचाव अभियान सफलतापूर्वक पूर्ण हो पाया।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान पुस्तक के लेखक श्री राजीव रंजन सिंह को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सकारात्मकता और अनुभवों से भरी यह पुस्तक निश्चित ही पढ़ने योग्य है।

इस अवसर पर भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष श्याम जाजू, पूर्व सांसद डश्र. रीता बहुगुणा जोशी और पुस्तक के लेखक राजीव रंजन सिंह उपस्थित रहे।

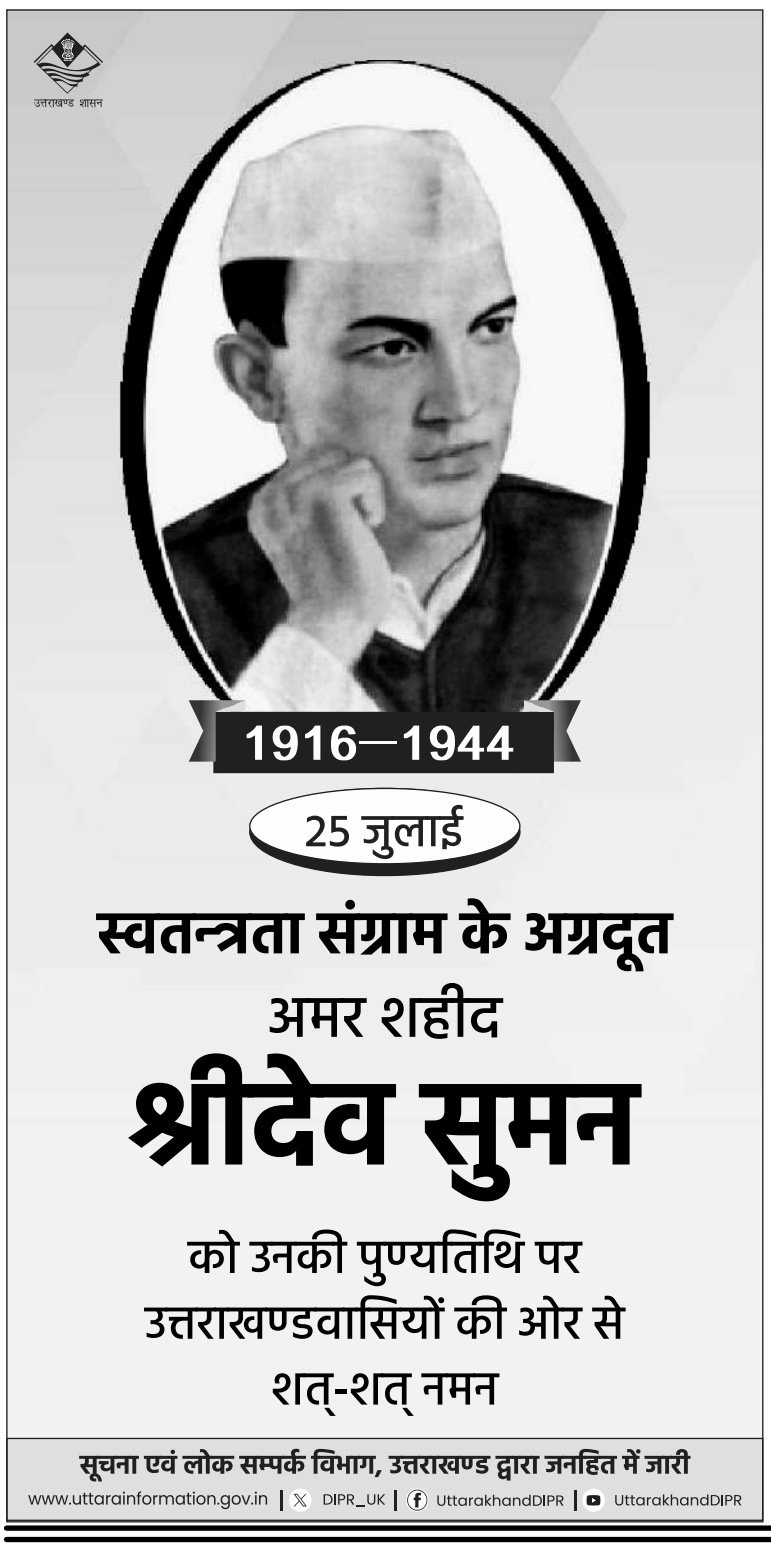

ईट राइट इंडिया अभियान से जुड़ेंगे शिक्षण संस्थानः डॉ. धन सिंह

देहरादून। प्रदेशभर के राजकीय शिक्षण संस्थानों को ईट राइट इंडिया अभियान से जोड़ा जायेगा। अभियान के तहत शिक्षण संस्थानों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में संचालित कैंटीनों में हाईजीनिक फूड प्रणाली विकसित की जायेगी। इसके लिये विभाग द्वारा प्रशिक्षण की ठोस कार्ययोजना तैयार कर कैंटीन संचालकों का प्रशिक्षण कराया जायेगा। इसके अलावा हेल्दी एंड हाइजिनिक फूड स्ट्रीट प्रोग्राम के तहत प्रथम चरण में प्रदेश के चार नगर निगम क्षेत्रों में फूड स्ट्रीट विकसित की जायेगी, जिसमें मिलेट्स से निर्मित खाद्य उत्पादों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने भारत सरकार द्वारा संचालित ईट राइट अभियान से प्रदेश के समस्त सरकारी शिक्षण संस्थानों को जोड़ने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी राजकीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों, आवासीय विद्यालयों तथा डायटों आदि में संचालित कैंटीनों में हाईजीनिक फूड प्रणाली को विकसित किया जायेगा ताकि यहां अध्ययनरत छात्र-छात्राओं एवं प्रशिक्षुकों को स्वस्थ व स्वच्छ भोजन परोसा जा सके। इसके लिये उन्होंने विभागीय अधिकारियों को एक माह के भीतर प्रशिक्षण की ठोस कार्ययोजना तैयार कर कैंटीन संचालकों एवं भोजनमाताओं को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये। विभागीय मंत्री ने कहा कि हेल्दी एंड हाईजिनिक फूड स्ट्रीट्स कार्यक्रम के तहत प्रदेश के चार निगर निगमों देहरादून द्धतरला नागलऋ, रूद्रपुर, नैनीताल तथा हरिद्वार में फूड स्ट्रीट विकसित की जायेंगी। जिसमें स्थानीय मोटे अनाजों से तैयार भोजन को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके लिये भारत सरकार द्वारा एक-एक करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने राज्य में जनऔषिधि केन्द्रों को बढ़ावा देने के साथ ही मेडिकल स्टोंरों पर फार्मासिस्टों की तैनाती सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। इसके साथ ही राज्य में फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ावा के लिये नई कंपनियों की स्थापना के लिये सिंगल विडो सुविधा प्रदान करने को कहा।

समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यो का पावर प्वाइंट के द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया। जिसमें विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया गया कि वर्ष 2024 में अबतक ड्रग्स के 313 सैम्पल लिये गये, जिसमें से 252 मानकों पर खरे पाये गये। जबकि 64 सैम्पल मानकों से निम्न पाये गये। जिसके तहत विभाग द्वारा 6 फर्मो के विरूद्ध डी एंड सी एक्ट तथा 8 फर्मा के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की गई, जबकि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2023-24 में खाद्य संरक्षा के तहत 1603 खाद्य पदार्थो के सैम्पल लिये गये, जिसमें से 28 सैम्पल असुरक्षित पाये गये। इसी प्रकार विभाग द्वारा चार धाम यात्रा मार्गो पर चलाये गये अभियान के तहत विभिन्न खाद्य पदार्थो के 601 सैम्पल की जांच की गई। जिसमें 529 असुरक्षित पाये गये बकि 72 नॉन कंफर्म पाये गये।

बैठक में अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ताजबर सिंह जग्गी, संयुक्त निदेशक खाद्य डॉ. आर.के. सिंह, उपायुक्त एफडीए जी.सी. कंडवाल, डॉ. सुधीर कुमार, डॉ. नीरज कुमार, जिला अभिहित अधिकारी पी.सी जोशी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे जबकि सभी जनपदों के जिला अभिहित अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री धामी ने आईटी पार्क स्थित आपदा प्रबंधन केंद्र से अतिवृष्टि की स्थिति पर जानकारी ली

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन केंद्र से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही अतिवृष्टि की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने जिलाधिकारियों को निरंतर समन्वय बनाए रखने के लिए निर्देश दिए और आवश्यकता पड़ने पर विस्थापन कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्धियों की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक कुल 315 करोड़ रुपये की धनराशि जनपदों को उपलब्ध कराई गई है और अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था भी की जाएगी।

चारधाम यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं रखने के उन्होंने निर्देश दिये हैं। यात्रा मार्ग में अतिवृष्टि के कारण यदि कहीं पर मार्ग बाधित होते हैं या आगे कोई खतरा प्रतीत होता है तो यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक लिया जाए।

इस अवसर पर उपाध्यक्ष राज्य सलाहकार समिति आपदा प्रबंधन विनय कुमार रूहेला, सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन आनंद स्वरूप, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन राजकुमार एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े अन्य अधिकारी उपस्थित थे

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में शिवभक्त कांवड़ियों के चरण धोकर किया स्वागत

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओम पुल घाट निकट डामकोठी, हरिद्वार में विभिन्न प्रदेशों से आए शिवभक्त कांवड़ियों के चरण धोकर, माल्यार्पण, शॉल और गंगाजली भेंट कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार पूरे देश की श्रद्धा का केंद्र है और यहां मां गंगा एवं भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रावण मास में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है और राज्य सरकार को कांवड़ियों का स्वागत करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने सभी कांवड़ियों से अपील की कि वे यात्रा का आनंद लेते हुए आत्मानुशासन का परिचय दें और शासन-प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

मुख्यमंत्री ने ओम पुल घाट पर आयोजित शिव समागम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार आस्था एवं विकास के साथ सनातन संस्कृति के संरक्षण का कार्य कर रही है। उन्होंने कांवड़ मेले के सुचारू प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन, संत महात्माओं, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं और स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग की सराहना की।

इस अवसर पर विधायक मदन कौशिक, पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप गोयल, आदेश चौहान, जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल आदि उपस्थित रहे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सुबोध भट्ट द्वारा दून वाणी प्रिंटर्स डी0एल0 रोड, देहरादून से मुद्रित एवं मोहकमपुर कलां, माजरी मी, पो0ओ0 नवादा, देहरादून, उत्तराखंड से प्रकाशित।
सम्पादक : सुबोध भट्ट मो0 9837383994, email : subodhbhatt09@gmail.com
Web site : harshitatimes.com, facebook page : harshitatimes.com, email : harshitatimes09@gmail.com,